RAJYA SABHA

Monday, the 13*th July*, 2009/22 *Asadha*, 1931 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*121.The questioner Shri Lalit Kishore Chaturvedi was absent. For answer *vide* page 21 *infra*]

मध्य प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.)

†*122. **श्रीमती माया सिंह** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2009-10 में कितनी धनराशि आबंटित की जाएगी; और

(ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 29 जिलों में स्वीकृत योजनाओं और 19 जिलों में लंबित योजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिन्दे): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत राज्यवार निधियों का आबंटन नहीं है। निधियों का संवितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के आधार पर किया जाता है।

(ख) 48 परियोजनाओं में से 32 परियोजनाएं अर्थात् 10वीं योजना की 8 परियोजनाओं तथा 11वीं योजना की 24 परियोजनाओं को आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है जिन्हें 11वीं योजनावधि के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है। अन्य शेष परियोजनाएं जिनमें मध्य प्रदेश की 16 परियोजनाएं शामिल हैं, को केवल 11वीं योजना के चरण-II के अंतर्गत स्वीकृति दी जा सकती है। 11वीं योजना के चरण-II को प्रारंभ करने हेतु सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

RGGVY in the Madhya Pradesh

†*122. SHRIMATI MAYA SINGH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the amount to be allocated to Madhya Pradesh under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY) for the financial year 2009-10; and

(b) by when all the sanctioned schemes in 29 districts and pending schemes in 19 districts of the State under RGGVY would be completed?

THE MINISTER OF POWER (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) There is no state-wise allocation of funds under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY). Funds are disbursed based on status of implementation of projects.

(b) Out of 48 projects, 32 projects *viz.* 8 projects of 10th Plan and 24 projects of 11th Plan have been sanctioned under RGGVY which are likely to be completed within the 11th Plan period. Any

†Original notice of the question was received in Hindi

remaining projects including 16 projects of Madhya Pradesh can only be sanctioned under Phase-II of 11th Plan. The commencement of Phase-II of 11th Plan is yet to be decided by the Government.

श्रीमती माया सिंह : चेयरमैन सर, माननीय मंत्री जी ने जो मेरे सवाल का जवाब दिया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कुल 48 परियोजनाओं का जिक्र किया है, जिनमें से 32 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस उत्तर से यह भी पता नहीं चलता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और उनके आधार पर कितनी धनराशि मध्य प्रदेश को मिलेगी?

सर, मध्य प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है। यह जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना है, यह बहुत अच्छी योजना है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या मध्य प्रदेश में कोई ऐसा सर्वे किया गया है जिससे यह पता चल सके कि वहां पर अभी तक कितने गांवों में बिजली नहीं पहुंची है? मुझे जानकारी मिली है कि कुछ प्रदेशों के प्रोजेक्ट्स आपके पास बाद में पहुंचे और उन राज्यों के प्रोजेक्ट्स पहले मंजूर हो गए और मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट्स को डिले किया गया? मैं जानना चाहती हूं कि आपका राज्यों के प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करने का क्या माप-दंड है? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि आपने किस आधार पर उनके प्रोजेक्ट्स को पहले सैंक्शन किया, जबकि उनकी डेट्स अलग-अलग थीं?

श्री सुशील कुमार शिंदे : सभापति महोदय, इसके लिए नार्म्स फिक्स-अप हो गए हैं। अभी तक देश में 61990 विलेजिज़ इलेक्ट्रिफाई हो गए हैं। इसमें बीपीएल को 2.34 करोड़ कनेक्शन देने हैं और electricity connections to BPL households के 62.6 लाख हो गए हैं। इसमे मध्य प्रदेश के सोलह डिस्ट्रिक्ट का काम बाकी रहा है। वह सेकेंड फेज़ में है, क्योंकि जो हमारा बैंच मार्क है, वह 13 लाख एक विलेज को है, जिन विलेज का टैरेन बहुत डिफिकल्ट है, उन विलेजेज को हम 18 लाख रुपये देते हैं। उनमें कहीं ज्यादा प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं, इसकी वजह से वह काम रुका हुआ है। जो प्रोजेक्ट्स लिमिट में थे, जो प्रोजेक्ट्स हमारे नार्म्स में बैठने वाले थे, वे प्रोजेक्ट्स फेज़ one में ले लिए गए हैं और जो नार्म्स के बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फेज़ two में ले लिया गया है। उन पर डिसकशन अभी भी चालू है।

श्रीमती माया सिंह : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के कितने प्रोजेक्ट्स आपके पास स्वीकृति के लिए आए और उनमें से कितने प्रोजेक्ट्स नार्म्स में अन-फिट थे, जिसकी वजह से आपने उनको कैंसिल किया या उनकी स्वीकृति नहीं दी?

सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है। मंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की 16 परियोजनाओं को अभी स्वीकृति के लिए पेंडिंग रखा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि उन परियोजनाओं की स्वीकृति कब तक मंत्री जी देंगे?

श्री सुशील कुमार शिन्दे : सर, जो परियोजनाएं नार्म्स में फिट नहीं बैठती हैं, उनको फेज़ two में ले लिया गया है और उसमें भी जो प्रॉयोरिटी लगाई है - जो naxalite areas हैं, जो hilly areas है, जो border areas हैं, उनको उस में लिया है। उसके अंदर जो भी परियोजनाएं मध्य प्रदेश की आ गई हैं, उनको ले लिया गया है। लेकिन मैं मालुमात के लिए बताऊंगा कि हमारा bench mark है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि विदिशा का बैंच मार्क 71 करोड़ का है, लेकिन वहां पर प्रोजेक्ट 79 करोड़ का आ गया है। इसी तरह से ग्वालियर के प्रोजेक्ट का 27 करोड़ का बैंच मार्क है और 52 करोड़ का वहां के लिए प्रपोजल आ गया है। इस वक्त हमारे को भारत सरकार ने टोटल Plan allocation में 28 हजार करोड़ दे दिया है और 7 हजार करोड़ की राशि अभी इस साल दे दी है। हम

इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर लगाकर कार्य कर रहे हैं। हम सेकंड फेज़ के लिए भी विशेषत: भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसे मांग रहे हैं और हमें यह पैसा जल्दी मिलने की आशा है।

श्री सभापति : श्री शिवानन्द तिवारी। ...(**व्यवधान**)... माया सिंह जी, आपके दो सवाल हो गए हैं।

श्रीमती माया सिंह : सर, जो प्रदेश विद्युत संकट झेल रहे हैं, मंत्री जी को उन पर खासतौर से ध्यान देना चाहिए।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : मैं जरूर ध्यान दूंगा और जहां पर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को स्वीकार करना पड़ता है, वहां पर पहली कंडिशन लिखकर देनी पड़ती है कि 6 से 8 घंटे तक हम बिना रुकावट के बिजली देंगे। यह फर्स्ट नार्म है। जहां पर बिजली कम है, तो उसके लिए मैं आपकी मालूमात के लिए बताऊंगा कि जो हमने 32 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए थे, उनमें मध्य प्रदेश के 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जहां एवार्ड भी नहीं हुआ है, वे मार्च, 2008 में किए हैं, डिंडोरी, मार्च 2008, मोरेना मार्च, 2008, नरसिंहपुर मार्च, 2008, सतना मार्च 2008, सिधी मार्च, 2008, दतिया फरवरी 2009, शिवपुरी फरवरी 2009, अनूपपुर मार्च 2008 और टीकमगढ़ मार्च, 2008। हमने इतने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, लेकिन अभी तक उस राज्य में उन पर अवार्ड ही नहीं हुआ है।

श्री शिवानन्द तिवारी : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत सिर्फ single फेज़ लाइन का प्रावधान किया जा रहा है? इससे घर में सिर्फ बिजली का बल्ब ही जलेगा। बिहार सरकार ने भी 3 फेज़ लाइन के लिए भारत सरकार को लिखा था कि अगर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत किया जाए, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की हालत खराब है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि single फेज़ लाइन दी जा रही है? अगर यह सही है, तो क्या राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 3 फेज़ लाइन कराई जाएगी? योजना के अंतर्गत लोड के अनुसार 3 फेज़ सप्लाई गांव तक पहुंचाई जा रही है। BPL घरों में कनेक्शन one फेज का दिया जा रहा है।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : अभी तक तो one फेज़ ही कर रहे हैं, लेकिन यह भी सोचने की बात है कि कई जगह ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं, जिसकी वजह से इस बारे में सोचना पड़ेगा और हम सोच रहे हैं।

श्री राजीव शुक्ल : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह बात सबने स्वीकार की है कि यह योजना बहुत अच्छी है। क्या यह बात सच है, चूंकि इसका इम्पलिमेंटेशन राज्य सरकारों के हाथ में है, तो प्रोजेक्ट्स के लिए जो ठेके देने का काम है, वह राज्य सरकार के स्तर पर होता है। उसमें इतनी देरी होती है और कई जगहों पर तो काफी करप्शन की शिकायत है, जिसकी जगह से यह योजना जिस स्तर पर लागू होनी चाहिए, उतनी नहीं हो पाती है। इस मामले में उनका क्या रेस्पॉन्स है?

श्री सुशील कुमार शिन्दे : यह बात सही है कि यह योजना राज्य सरकारें ही चलाती हैं। यदि राज्य सरकारें विनती करती हैं, तो हमारी PUSs उनको असिस्ट करती हैं। बहुत सी जगह इस पर विलम्ब हो रहा है और इम्पलिमेंटेशन के लिए 3 टायर मॉनिटरिंग कमेटी भी है। जिसके द्वारा भी प्रयास हो रहा है। हमारे पास REC में जो कम्पलेंट्स आती हैं, उसके लिए हम अपने ऑफिसर्स को भी भेज रहे हैं, लेकिन यह बात सही है कि कई राज्यों ने इसमें विलम्ब किया है।

श्री राजीव शुक्ल : क्या कोई मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं बना रहे हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट में बन रही है?

श्री सुशील कुमार शिन्दे : यह 3 टायर मॉनिटरिंग एजेंसी है। लोकल लेवल, REC और पावर मिनिस्ट्री, तीन जगहों पर मॉनिटरिंग होती है।

प्रो. राम गोपाल यादव : श्रीमन्, मध्य प्रदेश के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के संबंध में यह सवाल है। मैं माननीय मंत्री जी से सीधे ही यह जानना चाहूंगा कि विद्युतीकरण के जरिए गांवों को इलैक्ट्रिफाई किया जाता है। क्या आपने कोई सर्वे करवाया है कि मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत घरों में बिजली है? गांवों में बिजली लग जाती है, इलैक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, लेकिन एक गांव में और एक घर में भी बल्ब नहीं जलता है। हाउस होल्ड परसेंटेज इलैक्ट्रिफाई घरों का कितना है? क्या मध्य प्रदेश में इसका सर्वे हुआ है? क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कोशिश करेंगे?

श्री सुशील कुमार शिन्दे : सर्वे तो होता ही है। स्टेट की तरफ से DPR आता है कि कितने लोग BPL के हैं और above BPL कितने हैं? कितने घरों में बिजली नहीं है, उसी से ये डी.पी.आर. मंजूर किए जाते हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव : मैं यह जानना चाहता था कि कितने प्रतिशत घरों में बिजली है? क्या मध्य प्रदेश में आपने सर्वे कराया है? क्या आपने किसी एक जिले का भी करवाया है?

श्री सुशील कुमार शिन्दे : सभापति महोदय, सर्वे का सवाल ही नहीं उठता है। जो रिपोर्ट्स आती हैं, वह उसमें इनबिल्ट है, इसलिए सर्वे का सवाल ही नहीं उठता है। हम सब सैंक्शन कर देते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए।

Illegal mining at Obulapuram in A.P

*123. SHRI M.V. MYSURA REDDY:†
SHRI NANDAMURI HARIKRISHNA:
Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government has issued a directive to Andhra Pradesh Government to stop mining at Obulapuram mines in that State;

(b) if so, when such order was issued and the details of that order;

(c) whether the Ministry is aware that inspite of its directive, mining activity at Obulapuram is still going on in connivance with the officials and politicians in the State; and

(d) what immediate action the Ministry is proposing to take to stop illegal mining at Obulapuram?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri M.V. Mysura Reddy.